



"युद्ध अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"-वेदेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार

सम्पादकीय

जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र का नया युग

आखिरकार तमाम ऊहापोह, सुख्खा चुनौतियों तथा विदेशी दखल की तमाम आशंकाओं को निर्मूल करते हुए जम्मू-कश्मीर के जनमानस ने स्पष्ट सरकार बनाने का जनादेश दिया है। जनता ने विकास और शांति की आकांक्षा के साथ दिल खोलकर मतदान किया और अपनी उम्मीदों की सारकार चुनी है। घाटी में दशकों तक अब्दुल्ला परिवार के शासन के अनुभव के मद्देनजर घाटी के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा जताया। बुधवार को उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी सार्थक पहल यह रही कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर की राजनीति के दो ध्रुव बने कश्मीर घाटी व जम्मू क्षेत्र के जनमानस को साथ लेकर चलने का संकल्प दोहराया है। इस कड़ी में उमर अब्दुल्ला ने सुरिंदर चौधरी को राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उमर ने कहा भी कि 'चौधरी को मैंने इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाया, ताकि जम्मू के लोगों को महसूस हो सके कि उनकी भी राज्य की सत्ता में घाटी जितनी भागीदारी है। आगे भी ऐसे ही प्रयास हो रहे होंगे।' निस्संदेह, यह सकारात्मक राजनीति का उज्ज्वल पक्ष है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का। उल्लेखनीय है कि सुरिंदर चौधरी जम्मू से चुनकर आए हैं। नौशेरा से विधायक बने सुरिंदर चौधरी ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रान्त अध्यक्ष रवींद्र रैना को हराया था। बहरहाल, भले ही अब अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह गया, लेकिन इसके बावजूद जम्मू-कश्मीर के लोगों ने स्पष्ट जनादेश देकर एक स्थिर सरकार की बुनियाद ज़रूर रखी है। केंद्र शासित प्रदेश में एक दशक बाद हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का खासा उत्साह नजर आया। कहीं न कहीं जनता ने स्पष्ट संदेश भी दिया कि वे आतंकवाद व अलगाववाद से छुटकारा चाहते हैं। जाहिरा तौर पर नई सरकार के सामने व्यापक जनाकांक्षाओं को पूर्ण करने की चुनौती होगी। यह दायित्व सरकार को इस बात को ध्यान में रखकर निभाना होगा कि केंद्रशासित प्रदेश में उपराज्यपाल के पास व्यापक अधिकार हैं।

बहरहाल, ऐसे में नवनिर्वाचित सरकार और केंद्र का दायित्व है कि घाटी के लोगों को जिस मजबूत लोकतंत्र की आकांक्षा जतायी है, उसे पूरा करने में भरपूर सहयोग करें। एक समय राज्य में मतदाता उड़ के मारे मतदान करने हेतु नहीं निकलते थे। मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहता था। इस बार मतदाता निर्भीकता के साथ मतदान करने निकले। जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के संकल्प को सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया है। यद्यपि लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी नहीं मिल पायी थी, लेकिन जनता ने उन्हें राज्य में सरकार चलाने का स्पष्ट जनादेश दिया है। वहीं दूसरी ओर, इस भारी मतदान व स्पष्ट बहुमत का एक निष्कर्ष यह भी है कि लोग घाटी में शांति और सुकून चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा कि इस क्षेत्र में शांति कायम होने के साथ विकास की नई बयार चले। जिसमें आम नागरिक खुद को सुरक्षित अनुभव करते हुए राष्ट्रीय विकास की धारा के साथ-साथ कदमताल कर सकें। बहरहाल, जम्मू-कश्मीर में नई सरकार को व्यापक जनाकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए बदली हुई शासन व्यवस्था के साथ भी साम्य स्थापित करना है। इस बात का अहसास उमर अब्दुल्ला को भी है कि शासन चलाने में अब पहले जैसी स्वतंत्रता नहीं होगी क्योंकि राज्यापाल के पास व्यापक शक्तियां हैं। विवाहास किया जाना चाहिए कि कम से कम सीमावर्ती घाटी की संवेदनशीलता को देखते हुए इस केंद्रशासित प्रदेश में वैसा टकराव देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच देखने को मिलता रहा है। उम्मीद है कि आजीविए कि नये मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था से लेकर अन्य प्रशासनिक मामलों में एलजी के आगे लाचार नहीं होना पड़ेगा। विवाहास करें कि नई सरकार को प्रशासनिक मामलों में नौकरशाही का पर्याप्त सहयोग मिलता रहेगा। नीति-निर्णयों को ध्यान रखना होगा कि सरकार चलाने में किसी भी तरह का अनावश्यक व्यवधान कालांतर अशांति का वाहक बनेगा। उम्मीद करें कि यथाशीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रशासन की विंगसंतियां दूर की जा सकेंगी।



विश्वनाथ सचदेव-

उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कुछ हुआ और हो रहा है वह कोई नई बात नहीं लग रही। साम्रदायिकता की आग को हवा देकर मनुष्य को मनुष्य से दूर करने का खेल हमारी राजनीति का आजमाया हुआ हथियार रहा है। आजादी से पहले और आजादी प्राप्त करने के बाद भी अक्सर हमारे यहां धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम राजनीतिक ताकतें करती रही हैं। यह खतरनाक 'खेला' किताना राजनीतिक लाभ देता है या दे सकता है, यह कोई सि्पी हुई बात नहीं है। सच तो यह है कि साम्रदायिकता और जातीयता के नाम पर लोगों की राजनीति खर कर रहे हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि हमारे राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन का आधार जाति के सिमान्तों को बतारकर जातीयता या धर्म का ही सहारा लेते हैं। कोन-सा दल ऐसा है जो अपना उम्मीदवार तय करने के लिए यह नहीं देखता कि क्षेत्र विशेष में किस जाति या धर्म के लोग अधिक प्रभाषणशील हैं? यह एक पीड़ादायक सच्चाई है कि



विविधता में अपनी ताकत देखने वाला हमारा देश बंध जाति, भाषा, क्षेत्रीयता आदि के आधार पर भीतर भीतर लगातार बंटता जा रहा है? हमारे राजतंत्र कुछ भी कहे, पर राजनीतिक नफे-नुकसान का गणित अक्सर इलाका आधार पर तय होता है। यह एक शर्मनाक सच्चाई है। पर कितनों की रसम आती है इस सच्चाई पर? सच तो यह है कि हम इस सच्चाई से रुबरु होना ही नहीं चाहते। यदि ऐसा न होता तो कभी तो हम अपने राजतंत्रों से घुटने कि उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? क्यों अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए वे धर्म या जाति के नाम पर अपने के खतरों को समझना नहीं चाहते? आज भाजपा वाले कांग्रेस पर यह आरोप लगाते नहीं थकते कि वह गुटिकरण की राजनीति करती

रही है, अब भी कर रही है, और दूसरी ही सांस में उनकी सरकारों की राजनीति से दूर रखा जायेगा। पर देश ने यह आशा कब नहीं की थी कि देश और कब उसकी यह आशा पूरी हुई? जब बड़े-बड़े राजतंत्र बुनवाई समाजों में कफड़ों के आधार पर लोगों को पहचानने की बात करते हैं, मंगलसूत्र छीनने का हवाला देते हैं, मंदिर-मस्जिद के नाम पर राजनीति करते हैं, तो सवाल उठाना ही चाहिए कि यह सब कहे का अधिकार और अवसर उन्हें क्यों दिया जाये? जब हमने आजादी पायी थी तो अपने लिए धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना था। आज भी कुछ मुलाकार देश की जनता सर्वकर्म समावाह के आदर्श में ही विश्वास करती है लेकिन, आज भी कुछ लोग हैं हमारे देश में जो बंटवारे के समय रह गए कथित काम को अब पूरा करने की दुहाई दे

रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? आखिर वे चाहते क्या हैं? और क्यों ऐसी बात कहने वालों को बेनकाग नहीं किया जाता? बहुसंख्यकों को एकजुट होने के समय का हवाला देने वालों को क्या वही पूरा जाना चाहिए कि विश्वास, भगवान और राजनीति के बीच रेखाएं क्यों मीटायी जा रही हैं? जीवन में विश्वास और धर्म का अपना स्थान है-इन्हें राजनीतिक नफे-नुकसान के तराजू में तोलना जाना चाहिए। पर दुर्भाग्य से ऐसा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और यह काम बिना किसी हिचकिचाहट के हो रहा है। कहीं कहीं मुख्यमंत्री अपने राज्य में मंदिरों के विकास का आश्वासन दे रहा है तो कहीं चुनावी समाजों में बड़े राजतंत्रा धार्मिक नारे लगावना ज़रूरी समझने लगे हैं। हद तो तब हो जाती है जब ईश्वर-अल्लाह तera नाम कहना भी किसी राजतंत्र को खटकने लगता है। उनकी शिकायत यह है कि राष्ट्रपिता बापू के प्रिय भजन के यह शब्द तो मूल भजन में थे ही नहीं! इसे बीमार मानसिकता के अलावा और क्या संज्ञा दी जा सकती है? यह देश 140 करोड़ भारतीयों का है, हम सबका है। इसकी पहचान को किसी धर्म विशेष के नाम से जोड़े जाने की कर्दा आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों न हों, मूलतः हम सब भारतीय हैं। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम सब धर्मों को आदर की दृष्टि से देखते हैं। ईश्वर एक है, धर्म उस तक पहुंचने का मार्ग है। मार्ग भले ही अलग-अलग हों, पर सब पहुंचाते एक ही लक्ष्य

पर है। महात्मा गांधी जब 'सबको सम्मति दे भगवान' वाली बात कहते थे तो मनुष्य मात्र के कल्याण का सोच था इसके पीछे। सर्व भवतु सुखिनः वाले आदर्श में विश्वास करने वाली चेतना वाले देश में जब कोई राजतंत्र 'अंजाम बुरा होगा या तुबान काट ती जयेगी' जैसी बातें कहता है तो यह सवाल भी मन में उठता है कि ऐसी बातों को हम सहते क्यों हैं?

नहीं, हमें यह सब नहीं सहना। ऐसी बातों पर चुप्पी का मतलब एक मैन समर्थन ही हो सकता है। गलत बातों का ऐसा समर्थन अपराध ही है और पाप भी। धर्म के नाम पर समाज में दीवारें खड़ी करने वाले, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों, उस समाज के दुश्मन ही हैं जो दुनियाभर को बेतुल का तंत्र देने जाते हैं। यह वह मनीषीय समाज है जिसके आंगन में धर्म या जातीयता की दीवारें खड़ी करना अपने आप में एक गंभीर अपराध है। विवेकजाली नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऐसे अपराध करने वालों को सही राह पर चलने की प्रेरणा दे। 'बंटेंगे तो कटेंगे' जैसी बात का सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है- हम सब मनुष्य बने रहें। इसका और कोई भी अर्थ मनुष्यता के कलंक करने वाला है। अपने भीतर के मनुष्य को जगृत रखना ही हमारे अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सीतमती ज़रूरी थी और बिहार के भीतमती भी। ध्यान रहे, कर्दा बहराइच या सीतमती हमारे भीतर मनुष्यता की पराजय का ही प्रतीक है। यह पराजय किसी भी शर्त पर स्वीकार्य नहीं हो सकती।

—लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

एग्जिट पोल की गुणवत्ता पर उठती उंगलियां

प्रमोद भार्गव-

निर्वाचन आयोग ने 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र और 81 विधानसभा सीटों वाले आरखंड में चुनाव की घोषणा की है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि आरखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। साथ ही, 15 राज्यों की 48 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे, जिनके नतीजे उसी दिन आएंगे। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रियंका वाड़ा को उम्मीदवार घोषित किया है, यह सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया से एग्जिट पोल पर जिम्मेदारी से काम करने का आह्वान किया और ईवीएम को मतदान के लिए सुरक्षित बताया है।



वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल अनुमानों के विपरीत निकले हैं। इधर, हाल ही में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के अनुमान भी उल्टे पड़े। जो हरियाणा में कांग्रेस की भारी बहुमत हासिल कर लिया। विपक्ष ने एग्जिट पोल के आधार पर ईवीएम के जरिये सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में अक्सर आरोप लगते हैं कि विपक्ष यहां तो हल्ला करता है, जहां उसकी हार हो, लेकिन वहां शांत रहता है, जहां से उसे जीत मिलती है।

मतदाताओं को लुभाया है। एग्जिट पोल अनुमानों में कहा गया कि लाडली बहना, मुफ्त राशन, मुफ्त आवारा, आत्मनिर्भरता योजना जैसी योजनाओं से मिले लाभ के चलते ग्रामीण मतदाता राजग के पक्ष में दिखाई दिया है। रनी मतदाता मोदी को चुनने में आगे दिखाई दे रही है। परंतु परिणाम आने के बाद मीडिया की ये मुनाबियां गलत साबित हुईं। वर्ष 2019 की तुलना में वोटिंग क्रम रहने के बावजूद औसत मतदान 62 प्रतिशत से ऊपर रहा था। ये सर्वे यदि 4 जून को आने वाले वास्तविक नतीजों पर खरे उतरते तो राजग गठबन्धन स्पष्ट बहुमत में आ जाता। यही नहीं, इस संकेत तो लोभसभा के वनक के लिए राजग को सहयोगियों की जरूरत नहीं रहती है। ये अनुमान मतदाताओं को उन्के हकों के प्रति जागरूक किया। नतीजतन इस वर्ष के मतदाताओं ने राजग को भरपूर वोट दिए। कल गया कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे का लाभ गणतंत्र में ही उठाया। इसी का परिणाम है कि 2019 में मिस्री 18 सीटों की तुलना में भाजपा को वोट 21 से 28 सीटें मिलने तक का अनुमान बताया था। राम निंदर, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों ने सभी वर्ग के

आमंत्रण टुकराने का असर भी मतदाता पर पड़ा है। लगता है, अब छद्म धर्मनिरपेक्षता का आरण्य टूट रहा है। केवल बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं के तुष्टिकरण के लिए इसका सहारा ले रही हैं। ऐसा दिखने है कि इस बार भाजपा ने बंगाल को केंद्रित करके हमलावर राजनीति अपनाई है। नतीजतन, कमी वास्तविक बहुमत के आधार में शामिल होकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह भी कि ऐसे लोगों ने जहां भाजपा को मजबूती दी है, वहीं कम्युनिस्टों के इस गढ़ को विट्कल कमजोर करने का काम भी किया है।

धार्मिक उग्रवाद का बढ़ता खतरा



भूपिंदर सिंह-

खरगोश के साथ दौड़ना और शिकारी कुत्ते के साथ शिकार करना एक मुहावरा है जो पाकिस्तान के इ.गामिना के साथ निरंतर संबंध को सांशित करता है। जैसा कि इसका कायदे-आजम मुहम्मद अली जिन्ना ने विडंनानापूर्व कंग से प्रतिपादित किया था कि आप किसी भी धर्म या जाति या पंथ से संबंधित हो सकते हैं, इसका इस मूल सिद्धांत से कोई लेना-देना नहीं है कि हम सभी 'पवित्र भूमि' या पाकिस्तान में एक राज्य के नागरिक और समाज नागरिक हैं, जो दुनिया का एकमात्र देश है जो धर्म के नाम पर बनाया गया है। चूंकि जिन्ना के शब्द 'गामिना उल्लाह से परे थे, इसलिए 11 अगस्त 1947 को संविधान सभा में दिए गए इस केंद्रित भाषण की रिफॉरमड विधायिकात्मक रूप से 'खो गई' करकुल टोपी (जिसे 'जाना कैप' के नाम से जाना जाता है) पहले एक उदात्त दिखने वाले जिन्ना की औपचारिक तस्वीर करंसी नोटों के अलावा सरकारी इस्तरों पर दिखाई देती है। धर्मनिरपेक्ष होने की चाहत के अंतर्निहित विश्वासनाम विवरण गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक 'गामिना टिडरबॉक्स है जो फटने की धमकी देता है।

इस्लामाबाद ने एक बार फिर भारत में जन्मे इस्लामिक उपदेशक जाकिर हार्मिक के लिए लाल कालीन डिजाकर धार्मिक के अपने वेटेंट लीवर को लचीला बनाने का विकल्प देता है, जो आतंकवाद के विरोधकर्ता, घृणा फैलाने वाले भाषण, सांसायनिक विधेय को भड़काने आदि के आरोपों में भारत में वाहित एक मनीषा है। यह सुझाव देता है कि जाकिर नरकक व्यक्तित्व रूप से हथियार नहीं खाता है (वह ऐसा निहित रूप से करता है), ऐसी बातें स्पष्ट रूप से सुझाव देती हैं कि यह उसकी शिक्षाओं का अंधधुंधल बंधनव्यवहार, सशोधनवाद और करुणवाद है। जो असहिष्णुता, बहिष्कार और कट्टरता को जन्म देता है।

ऐसे विचारकों द्वारा भड़काए गए हिंसक आतंकवाद में फंसे राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह एक और आतंकवाद को बढ़ावा देने से बेहतर जानती है। धार्मिक नाना, उग्रवाद और असहिष्णुता को देवता हूँ जाकिर नाइक का आधिकारिक संवित्त पाकिस्तान के गहरे रूप से वाहित आतंकवादी का बंधनव्यवहार को कैंसे खंड कर सकता है, यह समझ से परे है। अपने संकीर्ण विचारों के अनुरूप, उपदेशकर्ता ने अनाथ लड़कियों को समर्थन करने वाले एक एन.पी.ओ. के कार्यक्रम के दौरान मंत्र से उत्तरकर विवाद खडा कर दिया। उनका चॉकना के अलावा स्पष्टीकरण यह था कि लड़कियां न-मह्रम (अर्थात्वाहित महिलाएँ) जो खून की रिसेतार नहीं हैं) थीं। यह बात बेगैरी से महिलाओं के प्रति घृणा का प्रदर्शन था।



